



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 190]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 9, 2019/आषाढ़ 18, 1941

No. 190]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 9, 2019/ASHADHA 18, 1941

## वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

### जांच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2019

**विषय :** यूरोपीय संघ तथा सिंगापुर के मूल के अथवा वहां से निर्यातित इसोनोनानोल (आईएनए), यूरोपीय संघ के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 2- प्रोपीइथेप्टाइल एल्कोहल (2-पीएच) तथा सउदी अरब तथा सिंगापुर के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 2- इथाइल हेक्सानोल (2-ईएच) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत।

**फा. सं. 14/22/2016 डी जी ए डी.—**मै. आंध्रा पैट्रोकेमिकल्स लि. (जिसे आगे “याचिकाकर्ता” अथवा “आवेदक” भी कहा गया है) ने समय समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) तथा समय समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे “नियमावली” भी कहा गया है) के अनुसार यूरोपीय संघ तथा सिंगापुर के मूल के अथवा वहां से निर्यातित इसोनोनानोल (आईएनए), यूरोपीय संघ के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 2- प्रोपीइथेप्टाइल एल्कोहल (2-पीएच) तथा सउदी अरब तथा सिंगापुर के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 2- इथाइल हेक्सानोल (2-ईएच) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे “प्राधिकारी” भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन प्रपत्र दायर किया है। इसोनोनानोल (आईएनए), 2- प्रोपीइथेप्टाइल एल्कोहल (2-पीएच) तथा 2- इथाइल हेक्सानोल (2-ईएच) को इसके बाद यहां “संबद्ध सामान” अथवा विचाराधीन उत्पाद “पी यू सी” कहा गया है। सऊदी अरब, यूरोपीय संघ और सिंगापुर को यहां आगे संबद्ध देश कहा गया है।

**क. पृष्ठभूमि :**

2. घरेलू उद्योग द्वारा दायर याचिका की जांच के आधार पर प्राधिकारी ने यह उल्लेख करते हुए दिनांक 7.6.2017 का कार्यालय ज्ञापन जारी किया कि प्राधिकारी याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित न किए जा रहे उत्पादों के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करना उपयुक्त नहीं पाते हैं। दिनांक 7.6.2017 के का.ज्ञापन का संगत उद्धरण निम्नलिखित है:

*"पाटनरोधी नियमावली के अनुसार अनुरोध की विस्तृत जांच के आधार पर प्राधिकारी याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित न किए जा रहे उत्पादों के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करना उपयुक्त नहीं पाते हैं। तथापि, घरेलू उद्योग यदि यह चाहता है, तो किसी भी ऐसे देश से 2- इथाइल हेक्सानोल (2-ईएच) के आयातों के संबंध में नया आवेदन दायर कर सकता है जिसके विरुद्ध शुल्क नहीं लगा हुआ है, यदि ऐसे देशों से आयात पाटित किए जाते हैं जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है।"*

3. और जबकि उपर्युक्त आदेश के विरुद्ध घरेलू उद्योग ने तेलंगाना के माननीय उच्च न्यायालय और हैदराबाद स्थित आंध्र प्रदेश सरकार के समक्ष 2017 की रिट याचिका सं. 25988 दायर की। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 9.2.2018 के आदेश द्वारा दिनांक 7 जून, 2017 के कार्यालय ज्ञापन को अलग कर दिया और प्राधिकारी को निर्देश दिया कि वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उनके समक्ष रखी गई पूरी सूचना का मूल्यांकन करने के बाद नए सिरे से याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग द्वारा दायर दिनांक 18.10.2016 और 02.12.2016 के आवेदन पत्रों पर विचार करें। 2017 की रिट याचिका सं. 25988 में पारित दिनांक 09.02.2018 के आदेश का संगत उद्धरण यहां नीचे दिया गया है।

*"तदनुसार दिनांक 7.6.2017 के कार्यालय ज्ञापन के रूप में गलत कार्यवाहियों को अलग करते हुए रिट याचिका की अनुमति दी जाती है और दूसरे उत्तरदाता को एतद्वारा निर्देश दिया जाता है कि वे अधिनियम के प्रावधानों और नियमावली विशेष रूप से नियम 2 (ख) और 2 (घ) के अनुसार उनके समक्ष रखी गई पूरी सूचना का मूल्यांकन करने के बाद नए सिरे से याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा दायर दिनांक 18.10.2016 और 2.12.2016 के आवेदन पत्रों पर विचार करें और इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से एक माह की अवधि के अंतर्गत उपयुक्त आदेश पारित करें।"*

4. तेलंगाना के माननीय उच्च न्यायालय और हैदराबाद स्थित आंध्र प्रदेश सरकार के उपर्युक्त आदेश के अनुसरण में, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने पूरी सूचना का मूल्यांकन पाटनरोधी नियमावली, 1995 के प्रावधानों के अनुसार और विशेष रूप से नियम 2(ख) और 2 (घ) के अनुसरण में करने और उपयुक्त आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। इस मामले में याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना का विस्तृत मूल्यांकन करने के बाद प्राधिकारी ने क्रमशः यूरोपीय संघ और सिंगापुर के मूल के अथवा वहां से निर्यातित इसोनोनानोल (आईएनए), 2- प्रोपीइथेप्टाइल एल्कोहल (2-पीएच) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने का निर्णय लिया क्योंकि घरेलू उद्योग केवल केवल 2-ईएच का उत्पादन कर रहा है परंतु वर्तमान याचिका में समान वस्तु के क्षेत्र के अंतर्गत 2-पीएच और आई एन ए शामिल हैं, (यद्यपि, उनका उत्पादन घरेलू तौर पर नहीं किया जाता)।

5. और जबकि उपर्युक्त आदेश के विरुद्ध घरेलू उद्योग ने तेलंगाना के माननीय उच्च न्यायालय और हैदराबाद स्थित आंध्र प्रदेश सरकार के समक्ष 2018 की रिट याचिका सं. 11116 पुनः दायर की। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 28.8.2018 के आदेश द्वारा प्राधिकारी के दिनांक 5.3.2018 के आदेश में अलग कर दिया और यूरोपीय संघ तथा सिंगापुर से कार्बन सं. 9 वाले आई एन ए और यूरोपीय संघ से कार्बन सं. 10 वाले 2-पीएच के आयातों के संबंध में यथा संभव शीघ्र कानून के अनुसार पाटनरोधी शुल्क निर्धारित करने के लिए जांच शुरू करने हेतु कदम उठाने का निर्देश दिया। 2018 की रिट याचिका सं. 11116 में पारित दिनांक 9.2.2018 का संगत उद्धरण नीचे दिया गया है :

*"9. उपर्युक्त के आलोक में इस रिट याचिका की अनुमति दी जाती है, दूसरे उत्तरदाता के आदेश को अलग करते हुए निर्देश दिया जाता है कि वे यूरोपीय संघ तथा सिंगापुर से कार्बन सं. 9 वाले आई एन ए और यूरोपीय संघ से कार्बन*

सं. 10 वाले 2-पीएच के आयातों के संबंध में यथा संभव शीघ्र कानून के अनुसार पाटनरोधी शुल्क निर्धारित करने के लिए जांच शुरू करने हेतु कदम उठाएं। ”

6. तेलंगाना के माननीय उच्च न्यायालय और हैदराबाद स्थित आंध्र प्रदेश सरकार के दिनांक 28.8.2018 के निर्देश के अनुसरण में मामले की जांच की शुरुआत करने के लिए प्राधिकारी ने 28.9.2018 और 24.10.2018 के पत्र जारी किए जिनमें याचिकाकर्ता से यह अनुरोध किया गया था कि वे डी जी टी आर की वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रपत्र के अनुसार पूर्ण दस्तावेजयुक्त याचिका दायर करें।
7. और जबकि प्राधिकारी के उपर्युक्त पत्रों के विरुद्ध घरेलू उद्योग ने एक बार फिर तेलंगाना के माननीय उच्च न्यायालय और हैदराबाद स्थित आंध्र प्रदेश सरकार के समक्ष 2019 की रिट याचिका सं. 2639 एक बार पुनः दायर की।
8. यह रिट याचिका 3.7.2019 को सूचीबद्ध की गई थी जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने प्राधिकारी का प्रतिनिधित्व करने वाले कानूनी अधिकारी को सलाह दी कि हाल के, अद्यतन, क्षति की अवधि और जांच की अवधि आदि से संबंधित सभी आंकड़ों सहित वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रपत्र के अनुसार पूर्ण दस्तावेजयुक्त आवेदन पत्र दायर करने के लिए घरेलू उद्योग से अनुरोध करना 2017 की रिट याचिका सं. 11116 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28.8.2018 को पारित आदेशों का उल्लंघन है और इसीलिए स्व-विवेक से अवमानना कार्यवाहियां शुरू करने और निर्दिष्ट प्राधिकारी को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पेश होने के लिए विवश थे। माननीय उच्च न्यायालय ने एक सप्ताह का समय दिया और इस मामले को 9.7.2019 को पोस्ट कर दिया।

#### ख. जांच की शुरुआत

9. उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी एतद्वारा तथाकथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने और पाटनरोधी शुल्क की राशि की सिफारिश करने पर विचार करने, जो यदि लगाई जाती है और घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, के लिए पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार तथाकथित और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति की पाटनरोधी जांच शुरू करते हैं।

#### ग. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) और समान वस्तु

10. विचाराधीन उत्पाद इसोनोनानोल (आईएनए), 2- प्रोपीइथेप्टाइल एल्कोहल (2-पीएच) तथा 2-ईएच है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि आई एन ए और 2-पीएच उनके द्वारा उत्पादित किए जा रहे 2-ईएच की समान वस्तु हैं। प्राधिकारी इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 28.8.2018 के आदेश को ध्यान में रखते हैं।

#### घ. संबद्ध देश

11. संबद्ध देश यूरोपीय संघ और सिंगापुर (आई एन ए और 2-पीएच के लिए), सिंगापुर (आई एन ए और 2-ईएच के लिए) और सउदीअरब (2-ईएच) के लिए हैं।

#### जांच की अवधि

12. याचिकाकर्ता ने जनवरी, 2016 से दिसंबर, 2016 तक की अवधि के लिए आंकड़े दायर किए हैं। उच्च न्यायालय के आदेश के मद्देनजर प्राधिकारी आवेदक द्वारा दिए गए आंकड़ों के आधार पर पाटन एवं क्षति का प्रथम दृष्टया मूल्यांकन कर जांच की शुरुआत करते हैं। तथापि, आगे जांच करने के लिए जांच की अवधि तथाकथित पाटन के कारण याचिकाकर्ता को क्षति होने तथा पाटन, क्षति होने का मूल्यांकन करने के लिए 1.4.2018 से 31.3.2019 माने जाने के लिए प्रस्तावित है।

#### सूचना प्रस्तुत करना

13. संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकार, भारत में उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले तकों व प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना उपलब्ध कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है।

कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत कोई अनुरोध नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है। सूचना/अनुरोध निम्नलिखित को प्रस्तुत की जा सकती है :

**निर्दिष्ट प्राधिकारी**  
**व्यापार उपचार महानिदेशालय**  
**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय**  
**वाणिज्य विभाग**  
**भारत सरकार**  
**चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001**

प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य पक्षों को उसे उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश भी प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

**समय-सीमा**

14. वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई के लिए कोई अनुरोध इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (दिनों 40) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
15. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जांच शुरुआत की तारीख से चालीस (40 दिनों) दिनों के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा पाटनरोधी उपायों को जारी रखने की जरूरत या अन्यथा के संबंध में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें। सूचना मूल प्रतियों और सॉफ्ट प्रतियों में अवश्य प्रस्तुत की जानी चाहिए।

**गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना**

16. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए उसके किसी भाग के संबंध में "गोपनीय" दावा करने के मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा:-
  - i. गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और
  - ii. अगोपनीय रूप में अंकित दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि)।
17. "गोपनीय "या" अगोपनीय "अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। दोनों पाठों की हार्ड कॉपियों के साथ साफ्ट कॉपियां चार (4) सैट में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।
18. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
19. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।
20. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त

सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

21. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

### सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

22. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

### असहयोग

23. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

### INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 9th July, 2019

**Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of Isononanol (INA) originating in or exported from European Union and Singapore, 2-Propylheptyl Alcohol (2-PH) originating in or exported from European Union and 2-Ethyl Hexanol (2-EH) originating in or exported from Saudi Arabia and Singapore.**

**F. No. 14/22/2016-DGAD.**—M/s Andhra Petrochemicals Ltd. (hereinafter also referred to as the ‘Petitioner’ or ‘Applicant’) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the ‘Authority’) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the ‘Act’) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as the ‘Rules’) for imposition of anti-dumping duty on imports of Isononanol (INA) originating in or exported from European Union and Singapore, 2-Propylheptyl Alcohol (2-PH) originating in or exported from European Union and 2-Ethyl Hexanol (2-EH) originating in or exported from Saudi Arabia and Singapore. Isononanol (INA), 2-Propylheptyl Alcohol (2-PH) and 2-Ethyl Hexanol (2-EH) are hereinafter referred to as the ‘subject goods’ or Product Under Consideration ‘PUC’. Saudi Arabia, EU and Singapore are hereinafter referred to as subject countries.

### A. Background

2. Based on examination of the petition filed by the Domestic Industry, Authority issued office memorandum dated 07.06.2017 stating that *the Authority doesn’t find it appropriate to initiate Anti Dumping Investigation concerning imports of the products not being produced by the petitioner domestic industry.* The Relevant extract of the office memorandum dated 07.06.2017 are under:

*“Based on the detailed examination of the request, as per anti dumping rules, the authority doesn’t find it appropriate to initiate Anti Dumping Investigation concerning imports of the products not being produced by the petitioner. However, the domestic industry, if so desired, may file fresh application, concerning imports of 2-Ethyl Hexanol (2-EH) from any country against which duty is not in place, if imports from such countries is dumped causing injury to the domestic industry”.*

3. And whereas against the said order, the Domestic Industry filed Writ Petition No. 25988 of 2017 before the Hon’ble High Court of Telangana and the State of Andhra Pradesh at Hyderabad. The Hon’ble High Court vide its order dated 09.02.2018 set aside the office memorandum dated 07<sup>th</sup> June 2017 and directed the Authority to consider the applications dated 18.10.2016 and 02.12.2016 filed by the petitioner domestic industry afresh after evaluation of the entire information placed before him in accordance with the provisions of the Act. The relevant extract of the order dated 09.02.2018 passed in Writ Petition No. 25988 of 2017 are reproduced as under:

*“ Accordingly, the writ petition is allowed setting aside the impugned proceedings in the form of office memorandum dated 07.06.2017 and the 2nd respondent is hereby directed to consider the applications dated 18.10.2016 and 02.12.2016 filed by the petitioner company afresh after evaluation of the entire information placed before him in accordance with the provisions of the Act and the Rules more particularly Rules 2(b) and 2(d) and pass appropriate orders within a period of one month from the date of receipt of a copy of this order.”*

4. Pursuant to the above stated order of the Hon’ble High Court of Telangana and the State of Andhra Pradesh at Hyderabad, wherein Hon’ble High Court has directed the Authority to evaluate the entire information in accordance with the provisions of the AD Rules, 1995 and more particularly in pursuance to Rules 2(b) and 2(d) and pass an appropriate order. After detailed examination of the information provided by the petitioner domestic industry in this case, Authority decided not to initiate anti- dumping investigation concerning imports of Isononanol (INA and 2- Propylheptyl Alcohol (2-PH) originating in or exported from European Union and Singapore, and European Union respectively as Domestic Industry is producing only 2-EH but the present petition included 2-PH and INA within the scope of like article, (though not produced domestically).
5. And whereas against the said order, the Domestic Industry again filed Writ Petition No. 11116 of 2018 before the Hon’ble High Court of Telangana and the State of Andhra Pradesh at Hyderabad. The Hon’ble High Court vide its order dated 28.08.2018 set aside the order of the Authority dated 05.03.2018 and directed to take steps for initiating investigation to determine the anti- dumping in respect of import INA having carbon No.9 from European Union and Singapore and 2-PH having carbon No.10 from European Union, in accordance with law, as expeditiously as possible. The relevant extract of the order dated 09.02.2018 passed in Writ Petition No. 11116 of 2018 are reproduced as under:

*“..9. In the light of the above, this writ petition is allowed, setting aside the order of the second respondent is directed to take steps for initiating investigation to determine the anti- dumping in respect of import INA having carbon No.9 from European Union and Singapore and 2-PH having carbon No.10 from European Union, in accordance with law, as expeditiously as possible.”*

6. Pursuant to the direction of the Hon’ble High Court of Telangana and the State of Andhra Pradesh at Hyderabad dated 28.08.2018 in order to initiate the case Authority issued letters dated 28.9.2018 and 24.10.2018 requesting the Petitioner to file a fully documented petition as per the prescribed proforma available on the DGTR’s website.
7. And whereas against the aforesaid letters of the Authority, the Domestic Industry once again filed Writ Petition No. 2639 of 2019 before the Hon’ble High Court of Telangana and the State of Andhra Pradesh at Hyderabad.
8. The writ petition was listed on 3.7.2019 wherein the Hon’ble High Court advised the law officer representing the Authority that requesting the industry to file fully documented application as per the prescribed proforma available on the website including all data related to recent, updated, period of injury and POI etc., is in violation of the orders passed by the Hon’ble High Court dated 28.8.2018 in W.P. No. 11116 of 2017 and therefore was inclined to initiate sumomoto contempt proceedings and directing the Designated Authority to appear before the Hon’ble High Court. The Hon’ble Court granted one weeks time and posted the matter on 9.7.2019.

#### **B. Initiation of investigation**

9. In view of the above, the Authority hereby initiates an AD investigation into the alleged dumping and consequent injury to the domestic industry in terms of rule 5 of AD rules to determine the existence, degree and effect of alleged dumping

and to consider recommending the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

**C. Product Under Consideration (PUC) and Like Article**

10. The PUC is considered as Isononanol (INA), 2-Propylheptyl Alcohol (2-PH) and 2-EH. The petitioner has claimed that INA and 2-PH are like article to 2-EH being produced by them. The Authority in this regard takes note of the Hon'ble High Court's order dated 28.8.2018.

**D. Subject Countries**

11. The subject countries are European Union and Singapore (for INA and 2-PH), Singapore (for INA and 2-EH) and Saudi Arabia (for 2-EH).

**E. Period of Investigation**

12. The petitioner has filed data for the period January 2016 to December 2016. In view of the High Court's order, the Authority initiates the investigation by prima facie evaluating dumping and injury based on the data provided by the applicant. However to investigate further the POI is proposed to be considered, as 1.4.2018 to 31.3.2019 to evaluate dumping, injury and Causality of injury to the petitioner due to alleged dumping.

**F. Submission of information**

13. The known exporters in the subject countries and their governments through their embassies in India, importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.

Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below. The information/submission may be submitted to:

**The Designated Authority  
Directorate General of Trade Remedies  
Ministry of Commerce & Industry  
Department of Commerce  
Government of India  
4th Floor, Jeevan Tara Building, 5, Parliament Street, New Delhi-110001**

Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

**G. Time-Limit**

14. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 days) from the date of the publication of this initiation notification. If no information is received within the prescribed time-limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.
15. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application within forty days (40 days) from the date of the publication of this initiation notification. The information must be submitted in hard copies as well as in soft copies.

**H. Submission of information on confidential basis**

16. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof:
- i. one set marked as Confidential (with title, number of pages, index, etc.), and
  - ii. the other set marked as Non-Confidential (with title, number of pages, index, etc.).
17. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. Soft copies of both the versions will also be required to be submitted, along with the hard copies, in four (4) sets of each.
18. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

19. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarised depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarisation is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
20. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in generalised or summary form, it may disregard such information.

Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

21. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorisation of the party providing such information.

**I. Inspection of Public File**

22. In terms of Rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

**J. Non-cooperation**

23. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Designated Authority